

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1101/2012/जोधपुर.
2. अपील संख्या - 1102/2012/जोधपुर.
3. अपील संख्या - 2271/2012/जोधपुर.
4. अपील संख्या - 2272/2012/जोधपुर.
5. अपील संख्या - 2273/2012/जोधपुर.
6. अपील संख्या - 2274/2012/जोधपुर.
7. अपील संख्या - 2275/2012/जोधपुर.
8. अपील संख्या - 2276/2012/जोधपुर.

मैसर्स अग्रवाल पोलीसेक्स लिमिटेड, सरदारपुरा, जोधपुर.अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर.
2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत-द्वितीय, जोधपुर.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री महावीर लूंकड़,
अधिकृत प्रतिनिधि

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/09/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये आठ अपीलें उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 02.03.2012 एवं 21.08.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, विशेष वृत-द्वितीय, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों वर्ष क्रमशः 2008-09, 2006-07, 2007-08 व 2009-10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 एवं वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन आठों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।





लगातार.....2

—: 2 :- 1-8. अपील संख्या-1101, 1102 एवं 2271 से 2276/2012/जोधपुर.

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी का आदेश क्रमांक व दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	क.नि.आ. दिनांक	अन्तर्गत धारा	सृजित मांग
1101/12	2/CST 02.03.2012	2008-09	10.01.2011	9 CST r/w 23 RVAT	5,36,591
1102/12	1/RVAT 02.03.2012	2008-09	10.01.2011	23 RVAT	11,23,446
2271/12	41/RVAT 21.08.2012	2006-07	14.09.2010	33 RVAT	17,87,977
2272/12	42/CST 21.08.2012	2006-07	14.09.2010	9 CST r/w 33 RVAT	4,73,566
2273/12	27/RVAT 21.08.2012	2007-08	05.03.2010	23/24 RVAT	8,13,198
2274/12	26/CST 21.08.2012	2007-08	05.03.2010	9(2) CST	4,16,563
2275/12	44/RVAT 21.08.2012	2009-10	06.01.2012	23 RVAT	5,77,042
2276/12	45/CST 21.08.2012	2009-10	06.01.2012	9 CST r/w 23 RVAT	3,81,765

4. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करते हुए रुपये 56,19,111/- का लाभ 11 वर्षों की अवधि के लिये यथा दिनांक 01.04.2006 से 12.06.2017 तक के लिये प्रदान किया गया, जिसके तहत अपीलार्थी व्यवहारी को 60 प्रतिशत कर मुक्ति का लाभ प्रदान किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी की कर निर्धारण अवधि वर्ष 2006-07 के लिये वेट अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम के तहत पारित मूल कर निर्धारण आदेशों दिनांक 29.01.2009 में व्यवहारी को कुल कर दायित्व का क्रमशः 60 व 50 प्रतिशत कर भुगतान में छूट प्रदान की गयी। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरणों में वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन आदेश दिनांक 14.09.2010 को पारित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 17 के अनुसार $[T = (O + R + P) - I = \text{Net Tax Payable} (\text{Output Tax} + \text{Reverse Tax} + \text{Purchase Tax}) - (\text{Input Tax}) = \text{Net Tax Payable}]$ व्यवहारी को कुल शुद्ध कर देयता पर 60 प्रतिशत करमुक्ति का लाभ प्राप्त होना अवधारित करते हुए तदनुसार आदेशों को संशोधित करते हुए व्यवहारी द्वारा प्राप्त कर लिये गये अधिक लाभ को वसूली योग्य अवधारित किया गया। इसी प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 के वेट अधिनियम की धारा 23 व केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत पृथक-पृथक पारित करते हुए उक्तानुसार व्यवहारी को शुद्ध करदेयता का 60 प्रतिशत लाभ प्राप्त होना अवधारित करते हुए, आदेश पारित किये गये एवं व्यवहारी द्वारा प्राप्त कर लिये अधिक कर लाभ को वसूलनीय अवधारित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।





लगातार.....3

5. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत II यूनिट को लाभ प्राप्त था। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005-171 दिनांक 31.03.2006 के तहत वेट अधिनियम की आस्थगन योजना के तहत विकल्प प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत व्यवहारी को आस्थगन योजना का लाभ प्रदान करते हुए एक राशि आस्थगित की गयी। Tax Payable का अर्थ वेट अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार Total Turnover पर Levied Tax है। वेट अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार प्रभारित कर जो धारा 2(24) के अनुसार Output Tax माना जाता है, की परिभाषा को ही Tax Payable के रूप में लिया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के मूल कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने व्यवहारी को योजना अनुसार लाभ प्रदान किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रकरणों को पुनः खोलते हुए मत भिन्नता के आधार पर संशोधित आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की गयी है, जो कि वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत अनुज्ञेय नहीं है। धारा 33 की परिधि अत्यन्त सीमित है, जिसके तहत केवल लिपिकीय/टंकण त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है। धारा 33 के तहत आदेश की मूल भावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 33 के तहत आदेशों को परिवर्तित करते हुए मांग सृजित किया जाना विधिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से भी त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया -

- (1) 29 टैक्स अपडेट पार्ट-7 पेज 253 (एस.सी.) ए.सी.टी.ओ. बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक
- (2) (1972) 30 एस.टी.सी. 321 (एस.सी.) जमील एण्ड कं0 व अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कुडप्पा
- (3) 34 टैक्स अपडेट पार्ट-3 पेज 102 (रा.क.बो.-खण्डपीठ) मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भीलवाड़ा
- (4) 35 टैक्स अपडेट पार्ट-1 पेज 22 (रा.क.बो.-खण्डपीठ) वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, उदयपुर बनाम मैसर्स ब्लूटोन पेपर प्रोडक्ट्स लि0 उदयपुर
- (5) 33 टैक्स अपडेट पार्ट-2 पेज 53 (रा.क.बो.-एकलपीठ) मैसर्स ओमेगा स्टोन्स प्रा0 लि0 किशनगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर





6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 54 वी.एस.टी. 161 (राज.) आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में 'Tax Payable' को परिभाषित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 17 के अनुसार शुद्ध देय कर को 'Tax payable' अवधारित किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतया आच्छादित है। अतः अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत आस्थगन योजना में कर लाभ प्रदान किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 के तहत विकल्प प्राप्त कर उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने की छूट प्रदान की गयी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 निम्न प्रकार है :-

FINANCE DEPARTMENT
TAX DIVISION
NOTIFICATION
Jaipur, March 31st, 2006

S.O. 471.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 20 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Rajasthan Act No. 4 of 2003) and by section 9 of the Central Sales Tax Act, 1956, the State Government hereby notifies that the industrial units mentioned in clause (1) shall be allowed to defer the payment of tax payable by them to the extent, in the manner and for the period as specified hereunder:

- (1) An industrial unit availing the benefit of exemption from tax under Sales Tax Incentive Scheme for Industries, 1987 (RST & CST) or Sales Tax New Incentive Scheme for Industries, 1989 (RST & CST) or the Rajasthan Sales Tax / the Central Sales Tax Exemption Scheme for Industries, 1998 or any specific notification issued with reference to these schemes by the Government from time to time (hereinafter referred to as Old Schemes), shall be eligible to avail the proportionate benefit under this notification. In such cases the cumulative benefit of exemption of tax already availed of and the benefit of deferment to be allowed under this notification shall not exceed the quantum of exemption sanctioned under the Old Scheme(s).





लगातार.....5

- (2) The unit may opt for the deferment benefits under this notification by submitting an application to the Assessing Authority in Form-A appended to this notification.
- (3) The Assessing Authority, after verification of the facts mentioned in the application and on being satisfied, shall issue Certificate of Eligibility in Form-B appended to this notification.
- (4) **An industrial unit shall be allowed to defer the payment of tax on sales made within the State or in the course of inter-State trade or commerce, of the goods for which the Eligibility Certificate was issued under the Old Schemes.**
- (5) The remaining eligible period under the Old Schemes as on the date of submission of the application completed in all respects, shall be extended equal to the remaining eligible period subject to a maximum period of five years.
- (6) The percentage of deferment of tax in the extended period shall be equal to the extent of the percentage of deferment of tax in the year immediately preceding such extension.
- (7) The unit shall pay the deferred tax of a quarter within a period of fifteen days of the end of the corresponding quarter after seven years without interest.
- (8) In case any such payment of deferred tax is not made in time, the total outstanding deferred amount as on the date of such default shall be recoverable immediately as arrears of land revenue along with interest from the first day of default of such payment. In such cases the deferment benefit under this notification may be withdrawn with the prior approval of Commissioner.
- (9) The industrial unit availing the benefit under this notification shall be eligible to issue Value Added Tax Invoice and to claim Input Tax Credit subject to the provisions of section 18.
- (10) The deferred tax for each tax period shall be adjusted against the balance amount of Eligible Fixed Capital Investment.
- (11) Where Input Tax Credit exceeds Output Tax for a tax period, it shall be carried forward to the next tax period(s).
- (12) The tax deferred under this notification shall be deemed to be a loan.
- (13) The units covered under the old schemes would be entitled to benefit of this notification only when it opts for deferment of tax both under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956.





- (14) All other terms and conditions of the Old Schemes not inconsistent with the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 or rules made thereunder and not covered under this notification, shall be applicable mutatis-mutandis to the unit availing deferment benefit under this notification.
- (15) The Certificate of Eligibility is liable to be amended/revoked cancelled, if obtained on misrepresentation or concealment of facts or by fraud or on breach of any of the terms and conditions, mentioned in the relevant notification.
- (16) This notification shall come into force on 1st day of April, 2006.

9. वेट अधिनियम की धारा 20 निम्न प्रकार है :-

20. Payment of tax. -

- (1) Tax payable under this Act shall be deposited into a Government treasury or a bank authorised to receive money on behalf of the State Government, on the basis of accounts of a dealer in such manner and at such intervals as may be notified by the State Government, and different intervals may be notified for different categories of dealers.
- (2) Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of works contract, an amount in lieu of tax shall be deducted by the awarder at such rate as notified by the State Government not exceeding six percent of the total value of the contract, in such manner and under such circumstances, as may be prescribed, from every bill of payment to a contractor and such sum shall be deposited or credited in the Government account within the specified time and in the prescribed manner.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, defer the payment of tax payable by any class of dealers, with or without interest, for any period on such conditions and under such circumstances as may be specified in the notification.
- (4) In case of any delay in payment of amount required to be deposited under any of the sub-sections (1), (2) and (3), the amount of interest under sub-section (1) of section 55 shall also be paid along with the amount of tax.



लगातार.....7

(5) Every deposit of tax or deduction of amount in lieu of tax made under this section shall be deemed to be provisional subject to adjustment against the tax liability determined in the assessment made under this Act.

(6) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, allow the dealer, availing the facility of deferment under sub-section (3), to make prepayment of the amount of deferred tax on such terms and conditions including the condition of remission from a part of deferred tax, as may be specified in such notification.

10. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 54 वी. एस.टी. 161 (राज.) आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के सदृश प्रकरण में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"Having heard the learned counsels on both sides, this Court finds little force in the contentions raised by Mr. Dinesh Mehta, learned counsel for the petitioner. In the absence of word 'tax payable' defined under the VAT Act, 2003 or RIPS, 2003 itself, it would be wrong to contend that the word 'output tax' and 'gross tax liability' under the Rajasthan VAT Act, 2003 should be construed to mean 'tax payable' under the VAT Act, 2003 for the purpose of RIPS, 2003. The very concept of VAT is to permit the assessee in the series of successive sales to pay only 'net tax liability' after deducting therefrom input tax paid by him to the seller of the goods and raw materials to him, so that cascading effect and repetitive tax liability on such successive sales is reduced and only the 'net tax payable' on the value addition made by the assessee is levied in his hands. The VAT regime therefore, does not require payment of output tax straightway by the assessee or manufacturer in question and it allows set off of input tax to such assessee or manufacturer. The words 'tax payable' employed in RIPS, 2003 particularly the words 'tax payable and deposited' used in clause 7 which gives interest subsidy and wage/employment subsidy clearly indicates that such subsidy will not exceed maximum limit of 50% of the 'tax payable and deposited' under the relevant Sales Tax Laws, like, RST Act, 1994, CST Act, 1956, and VAT Act, 2003. Not only clause (2) of clarification dtd. 10.10.2008, but all the six clarifications point and emphasize the deposit of tax before benefit of subsidy under Clause 7 of RIPS, 2003 can be given to the assessee. The contention of the learned counsel for the assessee, though attractive is devoid of

लगातार.....8

any merit and substance because it is hypothetical figure to construe 'tax payable' as the 'gross tax liability' or 'output tax' as defined in Section 2(24) of the VAT Act, 2003 which means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business. Section 17 of the Act with heading "Tax payable by a dealer" on the other hand clearly provides that tax payable by dealer is only after deducting input tax and letter "T" which defines net tax payable is O (output tax)+ R (Reverse Tax)+P (tax payable under Section 4(2)) – I (input tax). Therefore, the 'tax payable' under the Rajasthan VAT Act, 2003 is nothing but 'net tax payable' by the assessee or manufacturer as per Section 17 of the Act.

In the considered opinion of this Court, the clarification issued by the Finance Department (Tax Division) on 10.10.2008 is perfectly in consonance with the Rajasthan VAT Act, 2003 read with clause 7 of the Scheme – RIPS, 2003 and the same cannot be said to be either without jurisdiction or bearing incorrect or erroneous interpretation of provisions of the Scheme or VAT Act, 2003. Moreover, the subsidy provided under the RIPS, 2003 is a concession and there is no vested right of assessee or manufacturer to claim particular amount of subsidy upto a particular limit and the amount of subsidy could be curtailed or limited as has been done in clause 7 upto 50% of the 'tax payable and deposited' under the Rajasthan VAT Act, 2003 or CST Act, 1956 or erstwhile Rajasthan Sales Tax Act, 1994 putting a limit on such amount of subsidy which is computed on the basis of interest paid on the funds borrowed by the assessee and such clarification of such term cannot be said to be unjustified, illegal or arbitrary. The interpretation sought to be put by the learned counsel for the petitioner that 'tax payable' should be construed as 'gross tax liability' would be de hors the provisions of the Scheme itself and VAT Act, 2003 and therefore, such distorted interpretation cannot be put on the terms 'tax payable' and upon a harmonious and plain reading of said term in RIPS, 2003 and VAT Act, 2003 as given in clause 2 of the impugned clarification dtd. 10.10.2008 cannot be said to be arbitrary and illegal by any stretch of imagination and the same is found to be in consonance with the Act and the Scheme as per settled rules of interpretation of taxing statutes. The clarification dtd. 10.10.2008 being merely a clarification of interpretation of terms already existing would apply to all pending proceedings also and for the period prior to 10.10.2008, since the commencement of RIPS, 2003 itself and the impugned orders determining the cap of subsidy amount on the basis of net tax payable as well as the rectification orders to give effect to

the same to rectify the mistake apparent under the relevant powers under the Act and Scheme would be permissible in law and the impugned orders passed by the authorities are thus bound to be upheld."

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि tax payable से आशय net tax payable से है। अपीलार्थी को प्रोत्साहन योजना में दायित्वाधीन कर भुगतान की राशि में से अनुज्ञेय प्रतिशत कर के भुगतान को आस्थगित किया जावेगा व शेष कर राशि का भुगतान कोषागार में किया जायेगा। इस बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की व्यवस्था के पश्चात यह बिन्दु निर्णीत हो चुका है तथा कोई विवाद शेष नहीं रहता है। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर यह व्यवस्था पूर्णतया लागू होती है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में अन्तर्वलित प्रकरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं पहुंचाते हैं।

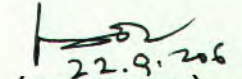
13. परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी की सभी आठ अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।


22.9.2016

(मनोहर पुरी)

सदस्य


22.9.2016
(मदन लाल)
सदस्य